



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58]
No. 58]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 12, 2003/चैत्र 22, 1925
NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 12, 2003/CHAITRA 22, 1925

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 9 अप्रैल, 2003

सं. टीएमपी/80/2000—सीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण दरमान की वैधता को आगे बढ़ाने और वेतन, मजदूरी और पेंशन के बकाया की देयता को पूरा करने के लिए विशेष दर निर्धारित हेतु कोलकाता पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव का एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार अनुमोदन करता है।

अनुसूची

मामला सं. टीएमपी/80/2000—सीपीटी

कोलकाता पत्तन न्यास (सीपीटी)

आवेदक

आदेश

(अप्रैल, 2003 के 4थे दिन पारित)

यह मामला दरमान की वैधता को आगे बढ़ाने और वेतन, मजदूरी और पेंशन के बकाया की देयता को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2004 तक विशेष दर निर्धारित करने हेतु कोलकाता पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1 कार्गो और जलयान-संबंधी प्रभारों के मामले में केओपीटी का दरमान पिछली बार 2001 में संशोधित किया गया था। इस संशोधन की वैधता दो वर्ष की अवधि के लिए थी और अगला संशोधन अप्रैल, 2003 में किया जाना है।

2.2 केओपीटी को वित्तीय वर्ष 2001-2002 से शुरू 4 वर्ष की अवधि के लिए दरमान में अधिसूचित विभिन्न प्रभारों के प्रतिशत के रूप में विशेष दर वसूल करने की अनुमति दी गई थी। वित्तीय वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के लिए विशेष दर पत्तन प्रयोक्ताओं द्वारा देय तत्संबंधी प्रभारों का 10 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। शुरू के दो वर्ष की अवधि की समाप्ति पर वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के पश्चात् अनुवर्ती अवधि के लिए विशेष दर की मात्रा निर्धारित की जाती है।

3.1 केओपीटी ने अब सूचित किया है कि उसने लागत को नियंत्रित करने और कार्गो की आवाजाही को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं और बिना सही विश्लेषण किए जल्दबाजी में दरमान तैयार करने से प्रतिकूल स्थिति पैदा हो सकती है। परन्तु, केओपीटी ने दरमान में सामान्य संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव और विशेष दर की वसूली के लिए प्रस्ताव नवम्बर, 2003 में प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया है।

3.2 केओपीटी ने 31 मार्च, 2001 तक प्रोद्भूत वेतन, मजदूरी और पेंशन लाभों के बकाया की कुल देयता 252.70 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया है। इसने 10 प्रतिशत की विशेष दर से प्राप्त राजस्व, आईसीआईसीआई से लिए गए ऋण और आंतरिक संसाधनों से इस देयता को 31 मार्च, 2003 तक 138.61 करोड़ रुपए कम कर दिया है। इसके अलावा 161.10 करोड़ रुपए की राशि शेष बकाया देयता भुगतान की विशेष दर और आईसीआईसीआई के ऋण की वापसी में कमी करके एवं आंतरिक संसाधनों से अर्जित की जा रही है।

4. इस परिप्रेक्ष्य में, यह प्राधिकरण वर्तमान दरमान की वैधता को 31 मार्च, 2004 तक की अवधि के लिए बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन करता है। वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिए यह विशेष दर लागू प्रभारों के 10 प्रतिशत वसूल की जाती रहेगी।

5. केओपीटी को दरमान में सामान्य संशोधन करने और 2003-2004 से आगे की अवधि के लिए विशेष दर की मात्रा से संबंधित अपना प्रस्ताव नवम्बर, 2003 में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2003/अस्त.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**NOTIFICATION**

Mumbai, the 9th April, 2003

No. TAMP/80/2000-CPT.—In exercise of the powers conferred by Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby approves the proposal of the Kolkata Port Trust for extension of the Validity of the Scale of Rates and the special rate fixed to meet the liability on account of arrears of salary, wages and pension as in the Order appended hereto.

SCHEDULE

Case No. TAMP/80/2000-CPT

The Kolkata Port Trust

Applicant

ORDER

(Passed on this 4th day of April, 2003)

This case relates to a proposal from the Kolkata Port Trust (KOPT) for extension of the validity of the Scale of Rates and the special rate fixed to meet the liability on account of arrears of salary, wages and pension upto 31 March, 2004.

2.1 The Scale of Rates of the KOPT with respect to cargo and vessel-related charges was last revised in April, 2001. The validity of this revision was for a period of two years and the next revision was due in April 2003.

2.2. The KOPT was permitted to levy a special rate as a percentage of various charges notified in the Scale of Rates for a period of 4 years commencing from the financial years 2001-02. The special rate for the financial years 2001-02 and 2002-03 was prescribed at 10% of the respective charges payable by port users. The quantum of the special rate for subsequent periods is to be fixed after a review of the financial position at the end of the initial two years period.

3.1 The KOPT has now informed that it has undertaken number of measures for cost control and increasing the cargo throughput and any hasty preparation of Scale of Rates without proper analysis may result in adverse situation. The KOPT has, however, assured to submit its proposal for general revision of Scale of Rates and the proposal for levy of special rate within November 2003.

3.2 The KOPT has estimated a total liability on account of arrear salary, wages and pension benefits accrued upto 31 March, 2001 at Rs. 252.70 crore. It has discharged this liability to the extent of Rs. 138.61 crore upto 31 March, 2003 out of the revenue generated from 10% special rate, loan from ICICI and internal resources. Further amount of Rs. 161.10 crore has to be generated from the special rate to discharge the balance arrear liability and recoup the ICICI loan repayment and internal resources.

4. In the backdrop, this Authority approves the proposal to extend the validity of the existing Scale of Rates for a further period upto 31 March, 2004. The special rate will continue to be levied at 10% of the applicable charges for the financial year 2003-04.

5. The KOPT is directed to submit its proposal for general review of Scale of Rates and its proposal regarding the quantum of special rate for the period beyond 2003-04 within November, 2003.

A. L. BONGIRWAR, Chairman

[Advt. III/IV/143/2003/Ext.]